प्रेस रिलीज़

डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोरः
उ.प्र. सरकार पूर्ण सहयोग के लिए तत्पर

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य मॉनिटरिंग समिति ने भूमि व अन्य अनापत्तियों के समाधान हेतु की बैठक
- मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना के लिए विचार–विमर्श

लखनऊ, 01 जून 2012: पूर्वी डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर (Eastern DFC) के अन्तर्गत परियोजनाओं के समयबद्ध व त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आज मुख्य सचिव, जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में इसकी राज्य मॉनिटरिंग समिति ने भूमि अधिग्रहण/पुनग्रहण व अन्य अनापत्तियों के समाधान हेतु बैठक की। बिन्दुवार मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर से संबंधित किसी भी कार्य में राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए।

बैठक में डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर कॉरपोरेशन के निदेशक–प्रोजेक्ट प्लानिंग, अंशुमान शर्मा सहित सभी संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

इसके पहले डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर कॉरपोरेशन के निदेशक–ऑपरेशन्स, पी.एन. शुक्ला ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आई.आई.डी.सी.), अनिल कुमार गुप्ता से मल्टी–मोडल पार्कों (बहुविध प्रचालनतंत्र) की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थानों का पहले कानपुर में, फिर राज्य के अन्य औद्योगिक व आर्थिक रूप से अनुकूल नगरों/ग्रामों , जो डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर के रूट में स्थित हैं, के चिन्हीकरण के संबंध में मुलाकात की।

आई.आई.डी.सी. ने जिलाधिकारियों और उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) को निर्देशित किया कि वे डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर कॉरपोरेशन के अधिकारियों से समन्वय कर डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर के एलाइनमेन्ट पर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया में गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर परियोजना के लिए हाई–वे व विद्युत संयोजन में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।

पंजाब में लुधियाना से पस्चिम बॉगो के दानकुनी तक 1839 किमी के प्रस्तावित पूर्वी डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर का लगभग 1000 किमी भाग उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से चन्दौली तक बनेगा। यह एक्सेस कन्ट्रोल्ड रेल कोरीडोर पूरी तरह से केवल 100 किमी/घण्टा की गति से चलने वाली मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर 15 जंकशन भी बनेंगे जो पहले से स्थापित रेलवे स्टेशनों व हाई–वे से जुड़ेंगे। डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर का 1499 किमी लम्बा पश्चिमी भाग भी बनेगा जिसमें उ.प्र. का 17–18 किमी लम्बा हिस्सा गौतमबुद्ध नगर में आएगा तथा यह प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू पार्ट ट्रस्ट, मुम्बई से जोड़ेगा।

डेडिकेटेड फ्रीट कोरीडोर के निदेशक–ऑपरेशन्स, पी.एन. शुक्ला ने बताया कि इस परियोजना के 2015–16 में पूर्ण होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि माल/उत्पाद के परिवहन का सीधा संबंध आर्थिक विकास से होता है। खासतौर पर पावर हाउस से संबंधित ईंधन व यंत्र, खाद, अनाज तथा पेट्रोलियम पदार्थों के समय से व सुरक्षित परिवहन का किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास पर बहुत असर पड़ता है।

मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों की स्थापना से न केवल सुगम व सुरक्षित माल–परिवहन सम्भव हो सकेगा अपितु इसके तहत गोदाम, कोल्ड–चेन, कन्ज़्यूमर उत्पाद के परिवहन तथा लॉजिस्टिक टाउन्स की भी स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पार्क की क्षेत्रफल लगभग 150 एकड़ होगा।